किसानों की मेहनत ने भारत को टॉप तीन में पहुंचाया : मोदी

गांधीनगर, प्रेट्र : किसानों की मेहनत और सरकारी नीतियों के संयुक्त प्रयास ने ही कुछ अनाजों और खाद्य उत्पादों के मामले में भारत को टॉप तीन देशों में शामिल कराया है। मंगलवार को गुजरात में ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। किसानों के खाते में साल में छह हजार रुपये की सहायता को उन्होंने सरकार का बड़ा कदम बताया।

युवा उद्यमियों को मौजूदा मुश्किलों से परेशान नहीं होना चाहिए। यह हालात बदलेगा। इसे बदलना ही होगा।
— दीपक पारेख
चेयरमैन, एचडीएफसी

सेंसेक्स 40,966.86 ▼ 188.26	निफ्टी 12,055.80 ▼ 63.20	सोना प्रति दस ग्राम ₹ 41,294 ▼ ₹162	चांदी प्रति किलोग्राम ₹ 47,870 ▼ ₹657	$ डॉलर ₹ 71.31 ▼ ₹0.12	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 59.17

चीन की अर्थव्यवस्था को बीमार बना रहा जानलेवा कोरोना वायरस

आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां झेल रहे चीन की आर्थिक सेहत को अब कोरोना वायरस बीमार करने में जुटा है। ऐसी समस्याओं से जूझने का चीन का पिछला अनुभव ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। माना जा रहा है कि चीन की चिंताओं को बढ़ाने वाला कोरोना वायरस उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं होगा। उधर, चीन के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। इस वायरस के प्रकोप के बाद चीन ने अपने मुख्य प्रांत हुबेई में तालाबंदी कर दी है। हुबेई की राजधानी वुहान ट्रांसपोर्ट हब के रूप में जानी जाती है। अगले आदेशों तक परिवहन के साधनों को यहां पर रोक कर रखा गया है।

दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संकट

चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी विकास दर में मामूली उतार-चढ़ाव भी वैश्विक मंदी को प्रभावित करने में सक्षम है। भारत की लुढ़कती अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए पहले से ही चिंता का विषय है। उस पर कोरोना वायरस का प्रकोप वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वालों और संचालकों के सिर का दर्द ही बढ़ा रहा है।

सार्स में डूबा था चीन

चीन में कोरोना वायरस के प्रभाव के सामने आने के बाद विशेषज्ञ पिछली महामारियों के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर के बारे में बात करने लगे हैं। 2002-03 में चीन सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) के वक्त डूब ही गया था। उस वक्त मरने वालों की दर कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों से ज्यादा थीं।

बीजिंग में लूनर नववर्ष के उपलक्ष्य में हुई लाइटिंग के सामने मॉस्क पहनकर सेल्फी लेता युवक। एएफपी

अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव

अनुमान है कि सार्स का प्रकोप चीन की अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक था। यहां तक की उसकी विकास दर को 1.1 से 2.6 फीसद तक प्रभावित किया था। इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रकोप सार्स की तरह ही विनाशकारी प्रभाव वाला हो सकता है। 2002-03 में चीन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर कम आश्रित और परस्पर संबंधित थीं।

लूनर नववर्ष की खुशी फीकी

लूनर नववर्ष चीन में छुट्टी और यात्रा का समय होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें लाखों लोग दुनिया के दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं। इस साल करीब 70 लाख लोगों ने विदेश यात्रा की योजना बनाई थी। हालांकि 2019 की तुलना में इस साल विदेश जाने वालों में करीब 40 फीसद की गिरावट देखी गई है। परिवहन बंद होने से उद्योगों के साथ आयात-निर्यात भी प्रभावित हुआ है। चीन इस वक्त दुनिया का विनिर्माण केंद्र है। परिवहन का लंबे समय तक बंद रहना दुनिया के दूसरे देशों पर भी असर डालेगा।

करोड़ों के नुकसान का अंदेशा

कोरोना वायरस ने चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला है, यह पूरी तरह तो बाद में ही पता चल सकेगा लेकिन शुरुआती अनुमान बताते हैं कि चीन की आर्थिक वृद्धि को 0.5 फीसद से एक फीसद तक प्रभावित कर सकता है। एक फीसद चीनी अर्थव्यवस्था का अर्थ 136 अरब डॉलर है और यह बहुत ज्यादा है। एशियन डवलपमेंट बैंक के अनुसार, सार्स के प्रकोप से चीन को 18 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। कोरोना वायरस का वैश्विक प्रभाव इससे बहुत ही ज्यादा होगा।

दिख रहा है असर

कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया के शेयर बाजारों में दिखने लगा है। चीन के शेनजेन और शंघाई कंपोजिट स्टॉक मार्केट में लूनर नववर्ष के लिए बंद होने से पहले क्रमश: 3.52 फीसद और 2.72 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। बाजारों में नकारात्मक भावनाओं को देखते हुए अगले सोमवार तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है।

तीन वर्षों में 56,000 करोड़ की होगी फूड टेक इंडस्ट्री

अनुमान ▶ 25-30 फीसद रह सकती है इस उद्योग की विकास दर

गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की सर्वे रिपोर्ट से सामने आई इस इंडस्ट्री की स्थिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : तेज रफ्तार डिजिटाइजेशन और बढ़ती ऑनलाइन शॉपिंग की बदौलत साल 2022 तक देश की ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का कारोबार आठ अरब डॉलर (करीब 56,000 करोड़ रुपये) के स्तर पर पहुंच जाएगा। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यह बिजनेस 25-30 प्रतिशत सीएजीआर (सालाना विकास दर के हिसाब से बढ़ रहा है। मंगलवार को जारी गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यंजनों में विविधता ऑनलाइन फूड ऑर्डर वाले एप्स के बार-बार इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजहों (35 प्रतिशत) में से एक है। यह कारोबार बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण आकर्षक छूट और खाने-पीने की चीजें घर बैठे मंगवाने में सहूलियत है।

फूड डिलिवरी की चुनौतियां

- **20** प्रतिशत लोगों को विभिन्न तरह के भरोसे की कमी
- **18** प्रतिशत लोग डिलिवरी चार्ज पसंद नहीं करते
- **13** प्रतिशत को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर आशंका
- **10** प्रतिशत ग्राहकों को खलती है मनमाफिक ऑर्डर की कमी

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब जोमैटो ने हाल ही में उबर का भारतीय फूड डिलिवरी बिजनेस खरीद लिया है।

गूगल की डायरेक्टर (ट्रेवल, बीएफएसआइ, क्लासीफाइड, गेमिंग, पेमेंट्स) रोमा दत्ता चौबे ने कहा, 'फूड टेक्नोलॉजी ने भारत के 500 से ज्यादा शहरों में अपनी पहुंच बना ली है। इस क्षेत्र की कंपनियों पर ग्राहकों का भरोसा हाल में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस उभरते बाजार में ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए कंपनियों के पास नए अवसर उपलब्ध हैं। नेटवर्क एडवोकेसी ने पहली बार भारत में लोगों को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की दिशा में प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका (52 प्रतिशत) निभाई है। इसके बाद इस मामले में विज्ञापनों की भूमिका 19 प्रतिशत रही है। खासतौर पर बड़े शहरों और देशभर के मध्यमवर्गीय तबके के बीच ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है।'

बढ़ रहा ऑनलाइन खर्च : बीसीजी के सीनियर पार्टनर और एमडी अभीक सिंघी ने कहा, 'फूड टेक स्टार्ट-अप्स ने भारतीयों के खाने का अंदाज बदल दिया है। अब ग्राहक होम-कुक्ड और हेल्थी खाने की मांग करने लगे हैं, जिससे बिजनेस के नए मॉडल सामने आ रहे हैं।'

निवेशकों को डुबोकर गुम हुई स्टार्ट-अप्स को मौका नहीं : टाटा

मुंबई, प्रेट्र : देश के शीर्ष उद्योगपतियों में एक रतन टाटा ने मंगलवार को कहा कि जो स्टार्ट-अप कंपनियां निवेशकों की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर गायब हो जाती हैं, उन्हें दूसरा या तीसरा मौका नहीं मिलने वाला है। टाटा संस के मानद चेयरमैन का यह भी कहना था कि भविष्य में पुराने जमाने के कारोबार खत्म होते जाएंगे और इनोवेटिव कंपनियों के युवा संस्थापक ही भारतीय उद्योग जगत के लीडर होंगे।

कई स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश कर चुके रतन टाटा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऐसी कंपनियों पर निवेशकों को भारी घाटे में डुबोने के आरोप लग रहे हैं। निवेशक भविष्य में कमाई की उम्मीद में स्टार्ट-अप कंपनियों में पूंजी लगाते रहते हैं और कंपनियां घाटे में चलती रहती हैं। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट को अपने परिचालन के लिए एक समय हर महीने 15 करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ रही थी। टाटा ने कहा कि हमारे सामने ऐसी स्टार्ट-अप कंपनियां आएंगी जो हमारा ध्यान खीचेंगी, रकम जुटाएंगी और गायब हो जाएंगी। इन्हें दूसरा या तीसरा मौका नहीं मिलने वाला है। स्टार्ट-अप कंपनियों को नैतिकता से कारोबार करना चाहिए और रातोंरात भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

एमएसएमई को बड़ी राहत मिलने की आस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नोटबंदी की मार से अभी तक जूझ रहे छोटे व मझोले उद्यमों को राहत देने की होगी बड़ी कोशिश
- नकदी भुगतान पर लगी रोक में ढिलाई देने पर भी हो रहा विचार
- पूंजी की दिक्कत को दूर करने के लिए विशेष फंड बनाने पर भी गंभीर विमर्श

प्रतीकात्मक फोटो

वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद से देश की छोटी व मझोली औद्योगिक इकाइयों की स्थिति जो खराब होनी शुरू हुई थी वह अभी तक नहीं सुधर पाई है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत के लिए बहुत हद तक इन इकाइयों की स्थिति को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे में शनिवार को पेश होने जा रहा आम बजट करोड़ों उद्योगों के लिए कई राहत भरी खबर ला सकता है। सूक्ष्म, लघु व मझोली इकाइयों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकातों में इस सेक्टर की स्थिति की सही तस्वीर रखी गई है। एमएसएमई को राहत देने को लेकर पिछले हफ्ते तक उच्चस्तरीय विमर्श हुआ है। नोटबंदी की वजह से इस सेक्टर को हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य तरीके से किए जाने की उम्मीद है।

मोदी के साथ इस सेक्टर की हुई बैठक में प्रमुखता से बताया गया है कि भारत जैसे बड़े व विकासशील देश में छोटे कारोबारियों के लिए नकदी का प्रचलन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है। नोटबंदी के बाद से जिस तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग पर दबाव बनाया गया है वह उलटा असर दिखा रहा है। छोटे छोटे उद्योगों में नकदी निवेश बंद हो चुका है। यह समूचे तंत्र में एक बड़ी बाधा के तौर पर चिन्हित हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार नकदी के इस्तेमाल को लेकर मौजूदा नियमों में राहत दे जो समूचे सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए जरुरी है। सरकार की तरफ से इस सेक्टर के लिए दूसरी अहम घोषणा इन्हें आसानी से वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए अलग से फंड बनाने का हो सकता है। पिछले छह महीने के दौरान सरकार व आरबीआइ से आश्वासन मिलने के बावजूद बैंक व एनबीएफसी अभी भी इन उद्योगों को कर्ज नहीं दे रहे हैं। अलग से फंड की घोषणा सेक्टर में नया उत्साह भर सकता है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के महासचिव अनिल भारद्वाज का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या अभी वर्किंग कैपिटल की कमी है। इसकी एक वजह है कि हजारों करोड़ सरकार व निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास फंसे हुए हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी रकम उन कंपनियों में फंसी हुई है जिनके खिलाफ दिवालिया कानून के तहत मामला दर्ज है। हमें सरकार से उच्च स्तर पर यह आश्वासन मिला है कि फंसे बकाये की रकम वापसी के लिए कुछ बजट में किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर ऐसा हो जाए तो रोजाना इस्तेमाल के लिए पूंजी की जरूरत पूरी हो जाएगी। इकोनॉमी में छोटे व मझोले उद्योगों की हिस्सेदारी 30 फीसद है और अभी जैसी इनकी हालत है उससे पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य वर्ष 2024 तक पूरा नहीं हो सकेगा।

झुनझुनवाला पर इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त होने का शक

जेएनएन, नई दिल्ली

▶ शिक्षा क्षेत्र की कंपनी एपटेक का है मामला, कंपनी में है झुनझुनवाला का बड़ा निवेश

घरेलू शेयर बाजार के सबसे सधे निवेशकों में एक राकेश झुनझुनवाला पर शिक्षा क्षेत्र की कंपनी एपटेक में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। खबरों के मुताबिक पूंजी बाजार नियामक सेबी इन आरोपों की जांच कर रहा है। एपटेक में झुनझुनवाला और उनके परिवार की निर्णायक हिस्सेदारी है। जांच के दायरे में झुनझुनवाला परिवार के वे सभी सदस्य शामिल हैं जो एपटेक में शेयरधारक हैं। निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों पर भी सेबी की नजर है, जिनमें जानेमाने निवेशक रमेश एस. दमानी और डायरेक्टर मधु जयकुमार शामिल हैं। किसी सूचीबद्ध कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति जब कंपनी की अंदरूनी जानकारी शेयर बाजार को दिए जाने से पहले उसके आधार पर शेयर की खरीद-फरोख्त करके गलत ढंग से कमाई करता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है।

अभी यह पता नहीं चला है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कब और किस सूचना के आधार पर हुई है। सेबी ने राकेश झुनझुनवाला के साथ उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला, भाई राजेश कुमार और सास सुशीला देवी गुप्ता को सेबी ने 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। झुनझुनवाला भी सेबी के जांच आधिकारी के सामने आए। झुनझुनवाला की बहन सुधा गुप्ता को 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सेबी ने एपटेक के डायरेक्टर उत्पल सेठ की बहन और रेयर एंटरप्राइज की सीईओ ऊष्मा सेठ सुले को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। रेयर एंटरप्राइज झुनझुनवाला की असेट मैनेजमेंट कंपनी है। एपटेक इकलौती कंपनी है, जिसमें झुनझुनवाला का निवेश और इसके प्रबंधन पर नियंत्रण दोनों है।

शेयरों में सफल निवेश के हुनर की वजह से राकेश झुनझनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। वह देश के सबसे अमीर व्यक्तिगत निवेशक हैं। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक झुनझुनवाला के पास करीब 11,140 करोड़ रुपये की शेयर संपत्ति है। यह पहला मौका नहीं है जब झुनझुनवाला सेबी की निगाह में आए हैं। वर्ष 2018 में भी बाजार नियामक ने जियोमेट्रिक में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर उनसे पूछताछ की थी। झुनझुनवाला ने बाद में कन्सेंट के साथ यह मामला 2.48 लाख रुपये चुकाकर सेटल कर लिया था।

फ्रॉड की जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए जवाबदेह नहीं होंगे बैंक प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत बैंक अधिकारियों द्वारा किए गए बड़े फ्रॉड के मामलों की जांच के अनुपालन की व्यक्तिगत जवाबदेही बैंक के एमडी और सीईओ की नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंकों के निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के सर्कुलर्स द्वारा तय की गई विभिन्न समयसीमाओं के अनुपालन के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था करें।

सरकार ने इस दिशा में कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया, 'इसी तरह 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले सभी फंसे कर्ज यानी एनपीए संबंधी खातों में धोखाधड़ी की अनिवार्य जांच संबंधी वित्तीय सेवा विभाग के 2015 के दिशानिर्देशों को केंद्रीय सतर्कता आयोग के 15 जनवरी, 2020 के सर्कुलर के साथ जोड़ दिया गया है। इसके तहत इस तरह के सभी संदिग्ध मामलों को शुरुआत में पूर्व सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी परामर्श बोर्ड (एबीबीएफएफ) के पास भेजने के लिए कहा गया है।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मौकों पर कहा है कि बैंकों के ईमानदारी से लिए गए वाणिज्यिक फैसलों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ऐसे मामलों में बैंकरों के बचाव के उपाय किए जाएंगे। वास्तविक कारोबारी विफलता और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के बीच फर्क को रखांकित किया जाएगा। बैंकरों के बीच बड़े स्तर पर ऐसी धारणा है कि यदि उनके द्वारा लिया गया कोई भी व्यावसायिक निर्णय गलत हो जाता है तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वित्त मंत्री ने बैंकरों की इस चिंता को दूर करने के लिए पिछले महीने एक बैठक बुलाई थी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के निदेशक भी उपस्थित थे। सीतारमण ने बैंकरों से यह भी कहा था कि इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर सीबीआइ के साथ विचार विमर्श, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि सब की आशंकाएं दूर की जा सकें। इस दौरान वित्त मंत्री ने बैंक प्रमुखों को भी काफी समय से लंबित सतर्कता मामलों को निपटाने के लिए कहा। उनका कहना था कि बैंकों को महाप्रबंधक की अध्यक्षता में पैनल बनाना चाहिए और तय समयसीमा में केस तैयार करने या फाइल बंद करने को लेकर फैसला लेना चाहिए।

- वित्तीय सेवा विभाग ने सरकारी बैंकों के बोर्ड को उचित व्यवस्था बनाने को कहा
- बैंकरों को अपने हर कारोबारी फैसले की विफलता पर नहीं होना होगा परेशान

प्रतीकात्मक फोटो

वित्त मंत्री से बैठक के आधार पर वित्त मंत्रालय ने बैंकों को वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया। यह कमेटी लंबित मामलों की प्रगति पर निगाह रखेगी। मंत्रालय का कहना है कि जांच में देरी से एक ओर कर्मचारियों का मनोबल टूटता है तो दूसरी ओर व्यवस्था की अक्षमता का कारण भी बनती है।

रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दे सकती है सरकार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

- वर्ष 2022 तक सबके लिए घर का सपना साकार करने में मददगार होगा यह कदम
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लाने से उद्योग को मिलेगी बड़ी मदद

लंबे समय से सुस्ती के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को आम बजट से इंडस्ट्री का दर्जा मिलने की उम्मीद है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह शनिवार को पेश होने के लिए प्रस्तावित बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिशा में कोई न कोई घोषणा कर सकती हैं। वर्ष 2022 तक सबके लिए घर का सपना तेजी से साकार करने के लिए भी इस तरह के कदम की जरूरत है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के कारोबारी सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित करने की भी मांग कर रहे हैं।

बिल्डरों को उम्मीद है कि बजट में होने वाली घोषणाएं और उपाय लंबे समय के लिए इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले होंगे। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले वर्ष के आखिरी महीनों में सरकार ने इस क्षेत्र को गति देने के लिए 25,000 करोड़ रुपये के एक फंड की घोषणा की है। अब बजट में रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से इसका समग्र विकास संभव हो सकेगा। रियल एस्टेट विशेषज्ञ विजय कुमार का कहना है कि इस क्षेत्र में लंबी सुस्ती का दौर है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं उसका सकारात्मक नतीजा आने वाले कुछ माह में दिखाई देने लगेगा। ऐसे में यदि बजट भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला होगा तो बात कुछ और होगी। एलान ग्रुप के एमडी रवीश कपूर का मानना है कि आगामी बजट से रियल एस्टेट क्षेत्र को भारी उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली कई घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। उम्मीद है कि इस बार यह इंतजार खत्म हो जाएगा।

बिल्डरों ने सरकार से कई तरह के अनुदानों की मांग भी की है। बजट में इस संबंध में भी घोषणा की उम्मीद है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस को लेकर सभी काफी आशान्वित हैं। इससे सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी होगा और किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में समय कम लगेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट विशेष में कदम उठाए जाने की जरूरत है।

मुश्किल हालात

अर्थव्यवस्था पर असर की चिंता में दुनियाभर के बाजार नरम, घरेलू शेयर बाजार भी लगातार दूसरे दिन गिरावट में रहे, सेंसेक्स में 188 अंक और निफ्टी में 63 अंक की गिरावट दर्ज

कोरोना के डर से नहीं उबर पाए शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : जानलेवा कोरोना वायरस का डर दुनियाभर के बाजारों पर हावी है। इसका असर घरेलू बाजारों पर भी दिख रहा है। इस वायरस ने चीन में बड़ी तादाद में लोगों को चपेट में ले लिया है। दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी इसके संदिग्ध मामले मिले हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर की आशंका में घरेलू और वैश्विक शेयर बाजारों में नरमी रही। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी में गिरावट आई। सेंसेक्स 188.26 अंक गिरकर 40,966.86 पर बंद हुआ। यह छह हफ्ते का निचला स्तर है। निफ्टी 63.20 अंक गिरकर 12,055.80 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा 4.55 फीसद का नुकसान हुआ। टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, आइटीसी, नेस्ले इंडिया और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा और एचडीएफसी बैंक के शेयर 1.53 फीसद तक बढ़कर बंद हुए। सेक्टर के हिसाब से टेलीकॉम में सबसे ज्यादा 4.11 फीसद की गिरावट आई। मेटल, एनर्जी, पावर, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। तेल एवं गैस, आइटी एवं फाइनेंस सेक्टर हरे निशान पर रहे। बीएसई के मिडकैप और स्मालकैप इंडेक्स में 0.52 फीसद तक की गिरावट आई।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'मांग में कमी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते ऑटो सेक्टर ने बाजार को सेटबैक दिया है। बीती तिमाही के नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे हैं, इसलिए निवेशक सतर्कता से कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट में यह चिंता है कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है।' मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 71.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

सोना-चांदी में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती से मंगलवार को सोने में गिरावट आई। स्थानीय सराफा बाजार में यह कीमती धातु 162 रुपये गिरकर 41,294 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोली गई। चांदी ने 657 रुपये का गोता लगाया। चांदी का भाव 47,870 रुपये प्रति किलो पर बोली गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में गिरावट दर्ज की गई।

इनमें रही गहमागहमी

एचडीएफसी : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में जबर्दस्त मुनाफे के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरों में उछाल आया। बीएसई में कंपनी के शेयर 1.53 फीसद की तेजी के साथ 2,432.40 रुपये पर बंद हुए। एनएसई में शेयर भाव 1.56 फीसद बढ़कर 2,433.40 रुपये रहा। कंपनी को बीती तिमाही में 8,372.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। सालभर पहले यह 2,113.8 करोड़ रुपये था।

यूनाइटेड स्पिरिट्स : बीएसई में कंपनी के शेयर 14 फीसद उछलकर 656.04 रुपये के भाव पर बंद हुए। एनएसई में 13.58 फीसद की बढ़त के साथ शेयर भाव 653.90 रुपये रहा। कंपनी के शेयरों में यह तेजी बेहतर तिमाही नतीजों के चलते देखी गई। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 15.19 फीसद बढ़कर 232 करोड़ रुपये रहा। सालभर पहले कंपनी का मुनाफा 201.4 करोड़ रुपये था।

इंटरग्लोब एविएशन : मुनाफावसूली के कारण इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में गिरावट आई। शुरुआती ट्रेडिंग में 3.23 फीसद की बढ़त लेने वाले शेयरों में आखिर में मुनाफावसूली हुई। बीएसई में कंपनी के शेयर 2.65 फीसद गिरकर 1,453.25 रुपये पर बंद हुए। एनएसई में कंपनी के शेयर 3.17 फीसद गिरकर 1,448.30 रुपये पर बंद हुए।

'एयर इंडिया को बेच जिम्मेदारी से बच नहीं सकती सरकार'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बीएमएस ने कहा - निजी उद्योगों को लाभ पहुंचाने का परोक्ष तरीका
- सामाजिक योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के नाम पर निजीकरण दुर्भाग्यपूर्ण

आरएसएस से संबद्ध यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने एयर इंडिया को बेचने के फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए सरकार से पुनर्विचार करने को कहा है। मंगलवार को जारी बयान में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वर्ष 1956 में निर्धारित औद्योगिक नीति के उद्देश्यों को पूर्ण रूपेण पूरा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के नाम पर उन्हें बेचा जा रहा है। निजी कंपनियों को पीएसयू की बिक्री से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि निजीकरण सरकार को उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करता।

संगठन का कहना है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करतीं। ऐसे अनेक मामले हैं जहां निजी कंपनियां अपने लिए संसाधन पैदा करने में विफल रही हैं। वे कर्ज के रूप में बैंकों (जिनमें ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं) से पैसा लेती हैं और फिर उसे चुकाने में असमर्थ रहती हैं। एनपीए संकट का ये एक बड़ा कारण है। पहले भी ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सरकार ने करदाताओं के पैसों से निजी कंपनियों या बैंकों को उबारा है। यह निजी व्यवसायों को धन आपूर्ति का परोक्ष तरीका है। जबकि मुनाफा कमाने पर ये कंपनियां सरकार को टैक्स चुकाने के अलावा कुछ नहीं देतीं। विरजेश ने कहा कि पब्लिक सेक्टर पर विचार करते समय हमें निष्पादन का पैमाना अपनाना चाहिए।